

आंध्र शुगर्स लिमिटेड व अन्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य।

29 सितम्बर 1967

[के.एन. वांचू, सी.जे., आर.एस. बछावत, वी. रामास्वामी,

जी.के. मित्र और के.एस. हेगड़े, जे.जे.]

आंध्र प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम 1961 (1961 का 45), धारा-21 की वैधता-कानून की बाध्यता के तहत कारखानों द्वारा चीनी की रीद-ऐसी लेन-देन क्या प्रविष्टि 54, सूची सातवीं अनुसूची, भारत का संविधान, 1950 धारा-21 1961 अधिनियम का 45 क्या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्या यह भारत के अनुच्छेद 301 के अर्थ के अंतर्गत मुक्त व्यापार वाणिज्य और संभोग में बाधा डालता है।

आंध्र प्रदेश (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम 1961 के तहत एक चीनी कारखाने के मालिक को गन्ना आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदना पड़ता था। उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत, राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा चीनी कारखाने में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए गन्ने की खरीद पर कर लगाने की शक्ति थी। कर प्रति मीट्रिक टन की अधिकतम दर के अधीन लगाया जा

सकता था। खांडसारी इकाइयों के लिए अधिकतम दर कारखानों की तुलना में कम थी; गुड के उत्पादन के लिए खरीदे गए गन्ने पर बिल्कुल भी कर नहीं लगाया जाता था। याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश के चीनी कारखाने थे। याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत धारा 21 की वैधता को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि याचिकाकर्ताओं व उनके एजेंटों को कानून द्वारा गन्ना, गन्ना उत्पादकों द्वारा खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी खरीद समझौतों के तहत नहीं की गई थी व प्रविष्टि 54 सूची-II के अंतर्गत गैरन डंकर्ले का मामला के अनुसार कर योग्य नहीं थे। आगे यह आग्रह किया गया कि कर माल के वजन के संदर्भ में लगाया गया, उपयोग के संदर्भ में लगाया गया और इसलिए यह एक उपयोग कर था, और यह कि कारखाने में माल का प्रवेश था, जिस पर कर लगाने की मांग की गयी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 301 उल्लंघन भी बताया गया।

अभिनिर्धारित किया: (i) उन्नीसवीं सदी में प्रचलित अहस्तक्षेप की अवधारणा का धीरे- धीरे क्षरण हुआ है। अब यह महसूस किया गया है कि सार्वजनिक हित में कुछ व्यवसाय करने वाले या एकाधिकार रखने वाले या लगभग एकाधिकार शक्तियों वाले व्यक्तियों पर कभी-कभी जनता की सेवा करने का कर्तव्य लगाया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो अनुबंध में प्रवेश करना चाहिए। गाँवों में बिखरे हुए गन्ना उत्पादकों के पास

वास्तविक सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं थी। गन्ना उत्पादकों और फैक्ट्री-मालिकों के बीच असमान प्रतिस्पर्धा में, कानून ने हस्तक्षेप किया और फैक्ट्री को निर्धारित नियमों और शर्तों पर गन्ना उत्पादकों द्वारा पेश किए गए गन्ने की खरीद के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया।  
[713 सी.एफ.]

1961 के अधिनियम 45 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ना उत्पादक फैक्ट्री के कब्जे वाले को गन्ने की बिक्री की पेशकश करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर वह कोई प्रस्ताव देता है, तो कारखाने का मालिक उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। परिणामी समझौता लिखित रूप में दर्ज किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित होता है। कारखाने के मालिक / अधिष्ठाता की सहमति, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 14 में परिभाषित अनुसार मुक्त है। कानून की बाध्यता, जबरदस्ती जैसा कि अधिनियम की धारा 15 में परिभाषित किया गया है।

समझौते कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं और बिक्री के अनुबंध हैं जैसा कि भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। इसलिए समझौते के तहत गन्ने की खरीद पर राज्य विधानमंडल द्वारा प्रविष्टि 54 सूची-II के तहत कर लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश

गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 21 तदनुसार अधिकारातीत नहीं है। [712 एफ- एच]।

मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकर्ले एंड कंपनी. [1959] एस.सी.आर. 379 और न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड, बनाम बिक्री कर आयुक्त, बी बिहार, [1963] सप्लिमेंट। 2 एस.सी.आर. 459, प्रतिष्ठित और समझाया गया।

लेन बनाम कॉटन, 1 एल.डी. रेम 646:91 ई.आर.17, किर्कनेस बनाम जॉन हडसन एंड कंपनी लिमिटेड [1955] ए.सी. 696 और रिज नॉमिनीज़ बनाम आई.आर.सी. [1962] 2 डब्ल्यू.एल.आर. 3, संदर्भित. द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बनाम मद्रास राज्य [1968] 1 एस.सी.आर. 479, पर भरोसा किया।

(ii) खरीद कर हमेशा माल की कीमत के संदर्भ में या टर्नओवर के संदर्भ में नहीं लगाया जाना चाहिए। यह किसी कारखाने के मालिक पर उसके द्वारा खरीदे गए सामान के वजन के आधार पर लगाया जा सकता है। [717 सी-ई]।

यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि खरीद कर हमेशा सामान पर ही लगाया जाना चाहिए और कभी भी उनके उपयोग, उपभोग या बिक्री के संदर्भ में नहीं लगाया जाना चाहिए। सूची-II प्रविष्टि 54 के तहत राज्य विधानमंडल गन्ने की सभी खरीद पर कर लगाने के लिए बाध्य नहीं है।

यह किसी कारखाने में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए आवश्यक गन्ने की खरीद पर कर लगा सकता है। इस प्रकार लगाया गया कर उपयोग कर नहीं है। [717 एफ-718 बी]।

मैकलियोड बनाम दिलवर्थ एंड कंपनी 322 यू.एस. 327: 88 एल. एड. 1305 और सी. जी. नायडू एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य, ए.आई.आर. 1953 मैड, 116, संदर्भित।

धारा 21 के तहत कारखाने में माल के प्रवेश पर कोई कर नहीं है। इस धारा के तहत कारखाने द्वारा उगाए गए गन्ने और उसके प्रवेश पर कर नहीं लगाया जा सकता है। [718 जी.]

डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1961] 3 एस.सी.आर. 242, संदर्भित।

(iii) धारा 21 मुक्त व्यापार, वाणिज्य और अंतर- एफ पाठ्यक्रम में बाधा नहीं डालती है और इसलिए अनुच्छेद 301 भारतीय संविधान का अपमान नहीं करती है। धारा 21 किसी भी आयातित गन्ने के साथ भेदभाव नहीं करता है। [719 ई-720 ए] ।

ए. टी. मेहताब माजिद एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य, [1963] सप्लिमेंट। 2 एस.सी.आर. 435, अतियाबारी टी कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य एवं अन्य। [1961] 1 एस.सी.आर. 809 और ऑटोमोबाइल

ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड, बनाम राजस्थान राज्य, [1963] 1 एस.सी.आर. 491, संदर्भित.

(iv) वैक्यूम पैन के माध्यम से चीनी का उत्पादन करने वाली फैक्टरियों, खुली पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन करने वाली खांडसारी इकाइयों और गुड के निर्माण के लिए गन्ने का उपयोग करने वाले गन्ना उत्पादकों के बीच अंतर व्यवहार उचित है और इसका अधिनियम के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है। [720 जी-एच]।

न ही धारा 21(3) के तहत छूट से भेदभाव होता है। ऐसे कारखाने जो नये हैं या जिनका सरकार की राय में काफी विस्तार हो चुका है। छूट वैध विधायी नीति पर आधारित है। यह प्रश्न कि क्या किसी कारखाने को छूट दी जानी चाहिए और यदि हां तो किस अवधि के लिए और यह प्रश्न कि क्या किसी कारखाने का पर्याप्त विस्तार हुआ है और यदि हां तो ऐसे विस्तार की सीमा का निर्णय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह राज्य के लिए संभव नहीं है

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, एपी राज्य (बछवाल, जे.)

विधानमंडल व्यक्तिगत मामलों की जांच करे और कार्य को उचित रूप से राज्य सरकार को सौंप गया था। सरकार के मार्गदर्शन के लिए

विधानमंडल अधिक कठोर मानक निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं थी।  
[721 ए- सी]।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 53,100,101, 105  
और 106/1967

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का  
प्रवर्तन हेतु याचिकाएँ।

एम.सी. सीतलवाड, ए.वी. कोटेश्वर राव, के. राजेंद्र चौ याचिकाकर्ताओं  
के लिए धुरी और के.आर.चौधरी (रिट याचिका संख्या 53/1967)।

एन.सी. चटर्जी, ए.वी. कोटेश्वर राव, के.राजेंद्र चौधरी और के.आर.  
चौधरी याचिकाकर्ताओं के लिए (रिट याचिका संख्या 100/1967 ए.वी.  
कोटेश्वर राव, के.राजेंद्र चौधरी और के.आर. चौधरी, याचिकाकर्ताओं के लिए  
(रिट याचिका संख्या 101/1967)

के.आर.चौधरी और के.राजेंद्र चौधरी, उत्तरदाताओं के लिए (रिट  
याचिका संख्या 105 और 106/1967) सी.के. दफ्तरी, अटॉर्न- जनरल और  
ए.वी.रंगम, डी उत्तरदाताओं के लिए (रिट याचिका संख्या 53/1967) पी.  
राम रेड्डी और ए.वी.रंगम उत्तरदाताओं के लिए डब्ल्यू. पी.एस.  
100/1967,101/1967, 105/1967 और 106/1967)।

सचिन चौधरी, जी.एल. सांघी और ओ.सी. माथुर, हस्तक्षेपकर्ता के लिए  
(रिट याचिका संख्या 53/1967)।

अदालत का फैसला- बचावत, जे. द्वारा दिया गया।

इन सभी रिट याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, याचिकाकर्ता यह घोषित करने वाले आदेश की मांग करते हैं। आंध्र प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1961 (आंध्र प्रदेश अधिनियम संख्या 45,1961) की धारा 21 असंवैधानिक और अधिकारातीत है और संबंधित पक्षों को धारा 21 के तहत कर लगाने से रोकने और पहले से वसूले गए कर को वापस करने के लिए निर्देश अधिनियम की धारा 21 निम्नानुसार है:

"(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी कारखाने में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए आवश्यक गन्ने की खरीद पर निर्धारित दर से पांच रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक कर नहीं लगा सकती है।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए कारखाने में उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले गन्ने के संबंध में इस तरह के कर को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर सकती है।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के तहत कर के भुगतान से छूट दे सकती है-

(ए) कोई भी नया कारखाना, जिसका सरकार की राय में, काफी विस्तार, विस्तार की सीमा तक, विस्तार के पूरे होने से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पर्याप्त रूप से विस्तार नहीं किया गया।

(4) उप- धारा (1) के तहत देय कर कारखाने के अधिभोगी से निर्धारित रूप से ऐसे प्राधिकारी द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा जो निर्धारित किया गया।

(5) कर के बकाया पर प्रति वर्ष नौ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

(6) यदि इस धारा के तहत कर, उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निर्धारित समय के भीतर किसी कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह ससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।"

धारा 2 (i) एक कारखाने को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "परिसर सहित कोई भी परिसर, जिसमें बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं या पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी हिस्से में कोई विनिर्माण प्रक्रिया जुड़ी हुई है, वैक्यूम पैन के माध्यम से चीनी का उत्पादन किया जा रहा है या

आमतौर पर यांत्रिक शक्ति की सहायता से किया जाता है या सामान्यतः किया जाता है। धारा 2 (एम) एक कारखाने के अधिभोगी को परिभाषित करती है। 1967 के अध्यादेश संख्या 1 द्वारा जिसे 1967 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, निम्नलिखित नई उप- धारा (I-A) सम्मिलित की गई और मूल अधिनियम की धारा 21 में अन्य परिणामी संशोधन किए गए।"

"(आई-ए) सरकार, अधिसूचना द्वारा, खांडसारी में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए आवश्यक गन्ने की खरीद पर तीन रुपये और पचास पैसे प्रति मीट्रिक टन से अधिक दर से कर नहीं लगा सकती है।

इसके अलावा निम्नलिखित उप- अनुभाग (केके) और (केके) भी धारा 2 मूल अधिनियम में डाले गये थे"

"(केके) 'खांडसारी चीनी'का अर्थ है खांडसारी इकाई में ओपन- पैशन प्रक्रिया द्वारा गन्ने के रस, या रब या गुड या दोनों से उत्पादित चीनी, जिसमें अस्सी प्रतिशत से अधिक सुक्रोज होता है (केकेके) 'खांडसारी इकाई' का अर्थ है खांडसारी चीनी के निर्माण में लगी या सामान्य रूप से लगी हुई इकाई और इसमें बेल भी शामिल है;"

यह उल्लेख किया जा सकता है कि गन्ने की बिक्री और खरीद को आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के तहत कर से छूट दी गई है। याचिकाकर्ताओं के पास धारा 2 (i) में परिभाषित चीनी कारखाने हैं। जैसा कि धारा 2 (एम) में परिभाषित है, उनके एजेंट कारखानों के मालिक हैं। उन्होंने अपने-अपने फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदा। राज्य सरकार ने धारा 21 के तहत कर लगाने की अधिसूचना जारी की थी। पिछले कई वर्षों से याचिकाकर्ताओं ने गन्ने की खरीद पर कर का भुगतान किया है और कर के भुगतान के लिए उनसे आगे की मांग की जा रही है। वे विभिन्न आधारों पर धारा 21 की शक्तियों और संवैधानिकता को चुनौती देते हैं। मुख्य प्रस्तुतियाँ श्री एमसी सीतलवाड द्वारा की गई थीं जो 1967 की रिट याचिका संख्या 53 में उपस्थित हुए थे और उनके तर्कों को अन्य याचिकाओं में उपस्थित वकील द्वारा अपनाया गया था। श्री एन.सी. चटर्जी, जो 1967 की रिट याचिका संख्या 100 में उपस्थित हुए थे, ने कुछ अतिरिक्त दलीलें उठाईं।

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, ए.पी. राज्य (बछवाल, जे.)

श्री सीतलवाड का कहना है कि धारा 21 जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा या उनकी ओर से अपने संबंधित कारखाने क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों से गन्ने की खरीद पर कर लगाने का सवाल है, यह प्रविष्टि संख्या के तहत विधायिका की शक्तियों के अधिकार के बाहर है। 54, सूची-II, मद्रास राज्य

बनाम के निर्णय के आलोक में संविधान की अनुसूची VIII। गैनन डंकर्ले एंड कंपनी मद्रास लिमिटेड, 1959 एससीआर 379 अब, गैनन डंकर्ले के मामले में, 1959 एससीआर 379 में वास्तविक निर्णय यह था कि विधायिका के पास भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची II, प्रविष्टि 48, अनुसूची VII के तहत भवनों के निर्माण के लिए संपूर्ण और अविभाज्य अनुबंध के तहत सामग्री की आपूर्ति पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन न्यायालय ने यह भी माना कि प्रविष्टि में "माल की बिक्री" वाक्यांश की व्याख्या उस कानूनी अर्थ में की जानी चाहिए जो भारतीय माल की बिक्री अधिनियम में थी, कि प्रांतीय विधानमंडल के पास ऐसे लेनदेन पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं थी जो बिक्री नहीं थी उस अर्थ में माल की और बिक्री का गठन करने के लिए मूल्य के लिए माल की बिक्री और ऐसे समझौते के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक समझौता होना चाहिए। वेंकटराम अय्यर, जे. ने पृष्ठ 397-398 (एससीआर के) पर कहा:

"इस प्रकार, इंग्लैंड और भारत दोनों के कानून के अनुसार, बिक्री के लिए यह आवश्यक है कि माल के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से पार्टियों के बीच एक समझौता होना चाहिए जो निश्चित रूप से अनुबंध करने की क्षमता को मानता है, कि यह धन के प्रतिफल द्वारा समर्थित होना चाहिए, और लेन- देन के परिणामस्वरूप संपत्ति

वास्तव में माल में स्थानांतरित होनी चाहिए। जब तक ये सभी तत्व मौजूद नहीं होते, कोई बिक्री नहीं हो सकती।"

इस निर्णय के आलोक में, प्रविष्टि 54, सूची-II, अनुसूची में अभिव्यक्ति

"माल की बिक्री "।

संविधान की VII की भी यही व्याख्या की जानी चाहिए। तर्क की समानता पर, इस प्रविष्टि के अंतर्गत "माल की खरीद"का गठन करने के लिए, ऐसे समझौते के अनुसार माल की खरीद और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक समझौता होना चाहिए। इसलिए, सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा या उनकी ओर से अपने- अपने कारखाने क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों से खरीदारी खरीद और बिक्री के समझौतों के तहत की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गन्ना आयुक्त को 1961 के अधिनियम संख्या 45 की धारा 15 के तहत किसी विशेष पेराई सत्र के दौरान किसी कारखाने को गन्ने की आपूर्ति के उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र को कारखाना क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।

धारा 16 (1) के तहत, फैक्ट्री क्षेत्र की घोषणा पर फैक्ट्री का अधिभोगी उस क्षेत्र में उगाए गए और फैक्ट्री को बिक्री के लिए पेश किए गए गन्ने की उतनी मात्रा खरीदने के लिए बाध्य है जितना कि गन्ना आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अनुसूची के प्रावधान. धारा 16

(2) किसी फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों को अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार किसी भी फैक्ट्री या अन्य व्यक्ति को गन्ने की आपूर्ति या बिक्री करने से रोकती है। अधिनियम के प्रावधान धारा 28(2)(1) के तहत सरकार को समझौते के प्रारूप के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। आंध्र प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) नियम 1951 के नियम 20 के तहत गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति आदेश के 14 दिनों के भीतर किसी क्षेत्र को फैक्ट्री क्षेत्र या गन्ना द्वारा तय किए गए विस्तारित समय के रूप में घोषित कर सकती है। आयुक्त, फैक्ट्री के अधिभोगी को उस क्षेत्र में उगाए गए गन्ने की आपूर्ति करने के लिए फॉर्म नंबर 2 में प्रस्ताव दें और फैक्ट्री के ऐसे अधिभोगी को प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर फॉर्म नंबर 3 या फॉर्म नंबर में एक समझौता करना होगा। 4 गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के साथ, जैसा भी मामला हो, प्रस्तावित गन्ने की खरीद के लिए। फॉर्म नंबर 3 गन्ना उत्पादक के साथ समझौते का वैधानिक रूप है। फॉर्म नंबर 3 में समझौते के द्वारा फैक्ट्री का अधिभोगी खरीदने के लिए सहमत होता है और गन्ना उत्पादक पेराई सत्र के दौरान क्षेत्र में कुछ गन्ने की फसल को सरकार द्वारा समय-समय पर नियमों और शर्तों पर अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर बेचने के लिए सहमत होता है। समझौते में उल्लेख किया गया है। समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल है और कारखाने के अधिभोगी

और गन्ना उत्पादक द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षरित है। गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के साथ फॉर्म नंबर 4 में समझौता उसी तर्ज पर है। समझौतों के सभी नियम और शर्तें और उनके प्रदर्शन का तरीका अधिनियम और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा तय और विनियमित होते हैं। अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का उल्लंघन धारा 23 के तहत दंडनीय है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के तहत तय किया गया है। विद्वान अटॉर्नी-जनरल और श्री राम रेड्डी ने तर्क दिया कि कारखाने के कब्जे वाले के पास गन्ना उत्पादकों से खरीदारी न करने का कुछ विकल्प है और समझौतों के नियमों और शर्तों के बारे में सौदेबाजी की कुछ स्वतंत्रता है। लेकिन अधिनियम और नियमों के सभी प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के बाद, उन्होंने इस बिंदु पर आगे नहीं बढ़ाया। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 1961 के अधिनियम संख्या 45 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ना उत्पादक अपना गन्ना फैक्ट्री को बेचने या न बेचने के लिए स्वतंत्र है। वह इसका उपभोग कर सकता है या इसे संसाधित करके गुड बना सकता है और फिर तैयार उत्पाद बेच सकता है। लेकिन यदि वह अपना गन्ना बेचने की पेशकश करता है, तो कारखाने का अधिभोगी उसके साथ निर्धारित नियमों और शर्तों पर एक समझौता करने और गन्ना आयुक्त

द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समझौते के अनुसार गन्ना खरीदने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि वे या उनके एजेंट कानून द्वारा गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उनकी खरीद समझौतों के तहत नहीं की जाती है और गैरन डंकरले के मामले के संबंध में प्रविष्टि संख्या 54, सूची II के तहत कर योग्य नहीं है। इस विवाद की बारीकी से जांच की आवश्यकता है।

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, ए.पी. राज्य (बछवाल, जे.)

भारतीय माल बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 4(1) के तहत, माल की बिक्री का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके तहत विक्रेता माल में संपत्ति को मूल्य के लिए खरीदार को हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। इस अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधान माल की बिक्री के अनुबंधों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि वे बाद के अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के साथ असंगत हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे कार्य या परहेज के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ भी करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, तो उसे एक प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता है। जब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है वह उस पर अपनी सहमति दे देता है, तो प्रस्ताव स्वीकार हो गया है माना जाता है। प्रस्ताव स्वीकार

होने पर वादा बन जाता है। प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक सेट एक दूसरे के लिए विचारणीय समझौता है। जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उस पर आपसी सहमति होती है और परिणामस्वरूप एक समझौता बनता है। धारा 10 के तहत सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे वैध विचार के लिए और वैध उद्देश्य के साथ अनुबंध करने में सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हैं और अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। धारा 13 सहमति को परिभाषित करती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति तब कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं। धारा 14 स्वतंत्र सहमति को परिभाषित करती है। सहमति तब मुफ्त मानी जाती है जब यह धारा 15 से 22 में परिभाषित जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती के कारण न हो। अब, 1981 के अधिनियम संख्या 45 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, गन्ना उत्पादक फ़ैक्टरी ज़ोन, फ़ैक्टरी के अधिभोगी को गन्ने की बिक्री का प्रस्ताव देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर वह कोई प्रस्ताव देता है, तो कारखाने का मालिक उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। परिणामी समझौता लिखित रूप में दर्ज किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित होता है। समझौते के लिए कारखाने के मालिक की सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती के कारण नहीं होती है। भारतीय अनुबंध

अधिनियम की धारा 14 में परिभाषित अनुसार उसकी सहमति निःशुल्क है, हालांकि वह समझौते में प्रवेश करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। जैसा कि धारा में परिभाषित किया गया है, कानून की बाध्यता जबरदस्ती नहीं है। अधिनियम के 15. बाध्यता के बावजूद, समझौता न तो अमान्य है और न ही रद्द करने योग्य है। कानून की नजर में समझौता स्वतंत्र रूप से किया जाता है। पार्टियाँ अनुबंध करने में सक्षम हैं। यह समझौता वैध विचार के लिए और वैध उद्देश्य के साथ किया गया है और कानून के किसी भी प्रावधान के तहत अमान्य नहीं है। समझौते कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं और भारतीय माल बिक्री अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित गन्ने की बिक्री के अनुबंध हैं। समझौते के तहत गन्ने की खरीद पर राज्य विधानमंडल द्वारा प्रविष्टि 54, सूची II के तहत कर लगाया जा सकता है।

बहुत पहले 1702 में, होल्ट, सी.जे. ने लेन बनाम कॉटन ("") में कहा था:

"जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार लेता है, तो जहां तक यह रोजगार चलता है, वह जनता की सेवा करने के लिए बाध्य है, अन्यथा इनकार करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।"

यह सिद्धांत कि जो कोई सार्वजनिक रोजगार लेता है वह जनता की सेवा करने के लिए बाध्य है, इसे सराय मालिकों और सामान्य वाहकों पर

लागू किया गया था। वैध बहाने के बिना, एक सराय का मालिक अपनी सराय में मेहमानों का स्वागत करने से इनकार नहीं कर सकता है, और एक सामान्य वाहक उसे दी जाने वाली गाड़ी के सामान को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। हेल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, तीसरा संस्करण देखें। वॉल्यूम. 4, अनुच्छेद 375 और खंड 21, अनुच्छेद 938। सिद्धांत के अधिक सामान्य अनुप्रयोग को अहस्तक्षेप के सिद्धांत के विकास से रोक दिया गया था, जो उन्नीसवीं सदी के मध्य में अपने चरम पर था। इसके बाद, अहस्तक्षेप की अवधारणा का धीरे-धीरे क्षरण हुआ है। अब यह महसूस किया गया है कि सार्वजनिक हित में, कुछ व्यवसाय करने वाले या एकाधिकार रखने वाले या लगभग एकाधिकार शक्तियों वाले व्यक्तियों पर कभी-कभी जनता की सेवा करने का कर्तव्य लगाया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो अनुबंध में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 की धारा 66 रेलवे प्रशासन को सामान्य किराए के भुगतान पर जनता को रेलवे पर यात्रा करने के लिए टिकट प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 22 एक लाइसेंसधारी को सामान्य नियमों और शर्तों पर आपूर्ति के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य करती है। चेशायर और फ़िफ़्ट अपने अनुबंध के नियम में, 6 वां संस्करण, पृ. 23 का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा के कारणों से राज्य व्यक्तियों को अनुबंध करने के

लिए मजबूर कर सकता है। 1961 के अधिनियम संख्या 45 का एक उद्देश्य कारखाना मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों से गन्ने की खरीद को विनियमित करना है। गाँवों में बिखरे हुए गन्ना उत्पादकों के पास वास्तविक सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं थी। फ़ैक्टरी मालिकों या उनकी कंपनियों को खरीदारी का लगभग एकाधिकार प्राप्त था और वे अपनी शर्तें खुद तय कर सकते थे। गन्ना उत्पादकों और फ़ैक्ट्री मालिकों के बीच इस असमान प्रतिस्पर्धा में कानून ने हस्तक्षेप किया और फ़ैक्ट्री को निर्धारित नियमों और शर्तों पर गन्ना उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित गन्ने की खरीद के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया।

इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य में न्यायालय ने माना कि लौह और इस्पात (उत्पादन और वितरण का नियंत्रण) के खंड 4 और 5 के तहत नियंत्रक द्वारा अधिकृत इस्पात उत्पादों की बिक्री ) आदेश, 1941 प्रविष्टि 54, सूची II के तहत कर योग्य थे। न्यायालय ने पाया कि पार्टियों ने बिक्री के अनुबंध में प्रवेश किया था, हालांकि आदेश के मद्दे नजर खरीदार और विक्रेता के बीच सौदे बाजी का क्षेत्र बहुत कम हो गया था, हेगड़े, जे. ने न्यायालय के लिए बोलते हुए कहा कि आर्थिक मजबूरियों और परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दृष्टिकोण में ठेकेदारी की स्वतंत्रता अब धीरे-धीरे संकीर्ण से संकीर्णतर सीमाओं तक सीमित होती जा रही थी। हमारे पास एक ऐसा मामला है

जहां बिक्री के अनुबंध में एक पक्ष को कठोर निर्धारित नियमों और शर्तों पर इसमें प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे सौदेबाजी की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन अनुबंध, फिर भी, बिक्री का अनुबंध है।

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, ए.पी. राज्य (बछवाल, जे.)

किर्कनेस बनाम में जॉन हडसन एंड कंपनी लिमिटेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बहुमत से माना कि परिवहन अधिनियम, 1947 की धारा 29 के तहत कंपनी के रेलवे वैगनों के स्वामित्व को ब्रिटिश परिवहन आयोग में अनिवार्य रूप से निहित करना बिक्री नहीं थी। आयकर अधिनियम, 1945 की धारा 17 में "बेचा गया है" वाक्यांश के अर्थ के भीतर। धारा 29 के तहत संपत्ति को अनिवार्य रूप से लेना था। लेने के लिए कंपनी की सहमति कानून द्वारा आवश्यक नहीं थी। कानून के बल पर, कंपनी की संपत्ति उसकी सहमति के बिना ले ली गई। कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई स्वीकृति नहीं थी, कोई आपसी सहमति नहीं थी और कोई अनुबंध नहीं हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि आपसी सहमति बिक्री के लेनदेन का एक तत्व थी। गैनन डंकर्ले के मामले में, 1959 एससीआर 379 में न्यायालय ने इस सिद्धांत को मंजूरी दे दी और वकील के तर्क को खारिज कर दिया कि किर्कनेस के मामले में शीर्षक का अनैच्छिक हस्तांतरण, विधायी प्रविष्टि के अर्थ के भीतर एक बिक्री थी। लेकिन अदालत ने यह नहीं कहा कि यदि एक पक्ष बिक्री की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र है और दूसरा पक्ष इसे

स्वीकार करने और माल की खरीद के लिए एक समझौते में प्रवेश करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है तो बिक्री का अनुबंध नहीं होगा। वर्तमान मामले में, विक्रेता एक प्रस्ताव देता है और खरीदार इसे स्वीकार कर लेता है। फिर पार्टियां लिखित रूप में एक समझौते पर अमल करती हैं और उस पर हस्ताक्षर करती हैं। इसमें आपसी सहमति और एक वैध अनुबंध होता है, हालांकि खरीदार की सहमति कानून की बाध्यता के तहत दी जाती है। श्री सीतलवाड ने पृष्ठ पर जीएच ट्रेडटल द्वारा अनुबंध के कानून में निम्नलिखित अनुच्छेद ५ पर भरोसा किया "जहां कानून किसी एक पक्ष के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ता है, वहां लेनदेन कोई अनुबंध नहीं है।

" लेकिन लेखक प्रस्ताव के समर्थन में किसी अधिकार का हवाला नहीं देता है। वह कहते हैं कि संपत्ति के अनिवार्य निपटान को भी किसी विशेष कानून के उद्देश्य के लिए अनुबंध के रूप में माना जा सकता है और रिज नॉमिनीज़ बनाम इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर, के मामले का हवाला दिया जाता है। वहां कोर्ट ने किर्कनेस, के मामले, को अलग करते हुए माना कि एक असहमत शेयरधारक के शेयरों का अनिवार्य हस्तांतरण उसकी ओर से एस के तहत हस्तांतरण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1948 का 209, जो हमारे कंपनी अधिनियम,

1956 की धारा 395 के अनुरूप है, स्टाम्प अधिनियम, 1891 की धारा 54 के अंतर्गत बिक्री पर धारा द्वारा बनाई गई मशीनरी के संबंध में था। लॉर्ड जस्टिस ने अलग-अलग राय दी। डोनोवन, एलजे की राय उद्धृत करना उचित है जिन्होंने कहा

"जब विधायिका, कंपनी अधिनियम, 1948 की धारा 209 द्वारा, अंतरिती कंपनी को अंतरणकर्ता कंपनी को भुगतान की जाने वाली कीमत के विरुद्ध अपने शेयरों के हस्तांतरण को निष्पादित करने के उद्देश्य से एक असहमत शेयरधारक की ओर से एक एजेंट नियुक्त करने का अधिकार देती है।

असहमत शेयरधारक के लिए विश्वास में, यह स्पष्ट रूप से उसकी असहमति को नजर अंदाज कर रहा है और उसे उसी स्थिति में डाल रहा है जैसे कि उसने सहमति दी थी। इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या इसके परिणाम स्वरूप बिक्री होगी, मुझे लगता है, किसी को उस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और शेयर धारकों की असहमति को उस सहमति द्वारा ओवरराइड माना जाता है जो कानून उस पर थोपता है, भले ही यह काल्पनिक हो। इस प्रकार, धारा 209 के संदर्भ में, स्थानांतरण कानून में बिक्री पर एक

हस्तांतरण बन जाता है। मेरी राय में यह निष्कर्ष हाउस ऑफ लॉर्ड्स यह निष्कर्ष, मेरी राय में, किर्कनेस (टैक्स इंस्पेक्टर) बनाम जॉन हडसन एंड कंपनी लिमिटेड, में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कही गई बातों के विपरीत नहीं है, जहां, विचाराधीन कानून के संदर्भ में, अन्य व्यक्तियों की संपत्ति को मुआवजे के भुगतान के विरुद्ध परिवहन आयोग में एक निर्दिष्ट तिथि पर निहित करने की घोषणा की गई थी। यह मशीनरी के अंतर से अधिक कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मशीनरी एक बिक्री और मुआवजे के विरुद्ध मात्र ज़ब्ती के बीच बहुत अंतर ला सकती है।

"लॉर्ड साइमंड्स, मैं सोचने का साहस करता हूं, जब वह कहते हैं कि उन्हें स्टॉप अधिनियमों के तहत तय किए गए मामलों से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो इसका तात्पर्य उतना ही है।"

मैसर्स में. न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त। बिहार न्यायालय ने बहुमत से माना कि चीनी और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1946 के तहत दिए गए चीनी नियंत्रक के निर्देशों के अनुपालन में एक चीनी कारखाने द्वारा प्रांतीय सरकार को चीनी की आपूर्ति बिक्री नहीं थी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची II, प्रविष्टि 48, अनुसूची VII के

तहत कर योग्य। श्री सीतलवाड ने शाह, जे. के पृष्ठ 469-470 के फैसले में निम्नलिखित अनुच्छेद पर मजबूत भरोसा जताया:

"इसलिए पार्टियों के बीच बिक्री का अनुबंध बिक्री के लिए एक पूर्व- आवश्यकता है। नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार निर्धारितियों द्वारा चीनी के प्रेषण का लेनदेन बिक्री के ऐसे किसी अनुबंध का परिणाम नहीं था। यह सामान्य आधार है कि मद्रास प्रांत ने नियंत्रक को चीनी की अपनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया, और नियंत्रक ने विनिर्माण इकाइयों से प्रांत को पूरी या आंशिक आवश्यकता की आपूर्ति करने का आह्वान किया। चीनी की आपूर्ति करते समय, नियंत्रक ने सामान खरीदने के लिए राज्य के एजेंट के रूप में कार्य नहीं किया: उसने अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया। प्रांत द्वारा चीनी खरीदने के लिए स्पष्ट रूप से कोई प्रस्ताव नहीं था, और निर्माता द्वारा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था निर्माता नियंत्रण आदेश के अधीन था और उसने कोई इच्छा नहीं छोड़ी: वह आदेश को पूरा करने से इनकार नहीं कर सकता था; यदि वह

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, बनाम ए.पी. राज्य (बचावत, जे.)  
ऐसा करने पर उसे आदेश के उल्लंघन के लिए दंडित किया  
जा सकता था और उसका सामान जब्त किया जा सकता  
था। प्रांत की सरकार और निर्माता के पास बातचीत करने  
का कोई अवसर नहीं था, और चीनी नियंत्रक के निर्देश के  
अनुसार भेजी गई थी, न कि सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव को  
स्वीकार करने के लिए।"

संदर्भ से हटकर, यह परिच्छेद इस तर्क को कुछ समर्थन देता है कि  
यदि प्रस्ताव की स्वीकृति किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश  
की बाध्यता के तहत की जाती है तो कोई अनुबंध नहीं हो सकता है।  
लेकिन परिच्छेद को मामले के तथ्यों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। चीनी  
और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1946 के खंड 3 द्वारा चीनी के उत्पादकों  
को कुछ सरकारों की ओर से चीनी प्राप्त करने के लिए नियंत्रक द्वारा विशेष  
रूप से अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर चीनी के निपटान पर प्रतिबंध लगा  
दिया गया था। खंड 5 के अनुसार प्रत्येक उत्पादक या डीलर को चीनी के  
उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और वितरण के संबंध में नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों  
का पालन करना होगा। खंड 6 ने नियंत्रक को चीनी की कीमत तय करने  
के लिए अधिकृत किया। खंड 7 (i) नियंत्रक को किसी भी प्रांत के लिए  
चीनी का कोटा आवंटित करने और चीनी की कीमत, मात्रा और प्रकार या

ग्रेड और आपूर्ति के समय और तरीके को निर्दिष्ट करते हुए चीनी की आपूर्ति के लिए किसी भी उत्पादक या डीलर को निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। . निर्देशों का उल्लंघन आदेश के खंड 11 के तहत स्टॉक को जब्त कर लिया गया और भारत की रक्षा नियम, 1939 के नियम 81 (4) के तहत दंडनीय था। पार्टियों के बीच लेनदेन का स्वीकार्य तरीका यह था कि उपभोग करने वाले राज्यों की सरकारें ऐसा करती थीं । चीनी नियंत्रक को अपनी चीनी की आवश्यकता के बारे में सूचित करते थे और कारखाने के मालिक उन्हें चीनी के अपने स्टॉक का विवरण भेजते थे । मांगों और स्टॉक के विवरण पर विचार करने पर, नियंत्रक आवंटन करता था। आवंटन आदेश नियंत्रक द्वारा फैक्ट्री मालिक को संबोधित किया जाता था, जिसमें उसे बाद के प्रेषण निर्देशों के अनुसार सरकार को चीनी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाता था। आवंटन आदेश की एक प्रति संबंधित सरकार को एक साथ भेजी जाती थी और बाद में फैक्ट्री को विस्तृत प्रेषण निर्देश भेजती थी। इन परिस्थितियों में, कपूर और शाह, जे.जे. (हिदायतुल्लाह, जे. ने असहमति जताते हुए कहा कि नियंत्रक को चीनी की अपनी आवश्यकता की सूचना देकर और चीनी के आवंटन के लिए आवेदन करके मद्रास सरकार ने निर्माता को कोई प्रस्ताव नहीं दिया। निर्माता को नियंत्रक का निर्देश। निर्माता को चीनी की आपूर्ति करने के लिए नियंत्रक का निर्देश सरकार को उसके वैधानिक अधिकार का प्रयोग

करते हुए दिया गया था और यह सरकार द्वारा किए गए किसी प्रस्ताव का संचार नहीं था। नियंत्रक के निर्देशों के अनुपालन में माल का प्रेषण निर्माता द्वारा किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं थी और न ही इसे निर्माता द्वारा माल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव माना जा सकता है। उस मामले के विशेष तथ्यों पर, बहुमत का निर्णय यह था कि कोई प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं हुई और कोई अनुबंध नहीं हुआ।

उस निर्णय को इस प्रस्ताव के प्राधिकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि किसी क़ानून की बाध्यता के तहत बिक्री का कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और लेन-देन को विनियमित करने वाले विशेष क़ानून की शर्तों पर निर्भर करता है कि पार्टियों ने माल की बिक्री के अनुबंध में प्रवेश किया है या नहीं। 1961 के अधिनियम संख्या 45 के तहत, एक गन्ना उत्पादक सीधे कारखाने के मालिक को एक प्रस्ताव देता है और वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर पार्टियां लिखित रूप में एक समझौता बनाती हैं और उस पर हस्ताक्षर करती हैं। इस प्रकार पार्टियों के बीच अनुबंध की प्रत्यक्ष गोपनीयता होती है। अनुबंध गन्ने की बिक्री और खरीद का अनुबंध है, हालांकि खरीदार एक क़ानून की बाध्यता के तहत अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राज्य विधानमंडल ऐसे

अनुबंध के तहत की गई बेंट की खरीद पर कर लगाने में सक्षम है ।

श्री सीतलवाड ने प्रस्तुत किया कि गन्ने के टन भार के संदर्भ में कोई खरीद कर नहीं लगाया जा सकता है। हम इस विवाद को स्वीकार नहीं कर सकते. आमतौर पर खरीद कर सामान की कीमत के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन विधायिका खरीदे गए सामान के वजन के आधार पर कर लगाने में सक्षम है।

श्री चटर्जी का यह तर्क कि खरीद कर केवल टर्नओवर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, समान रूप से निराधार है। जहां किसी डीलर पर खरीद कर लगाया जाता है, तो लेवी आमतौर पर उसके टर्नओवर के संदर्भ में होती है, जिसका मतलब आम तौर पर खरीद कीमतों की कुल राशि से होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि टैक्स किसी डीलर पर या उसके टर्नओवर के आधार पर लगाया जाए। यह किसी कारखाने के मालिक पर उसके द्वारा खरीदे गए सामान के वजन के आधार पर लगाया जा सकता है।

श्री चटर्जी ने आगे कहा कि आम तौर पर वस्तुओं पर खरीद कर लगाया जाना चाहिए, और उनके बाद के उपयोग, उपभोग या बिक्री के संदर्भ में कोई खरीद कर नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने तर्क को पैराग्राफ 17 से 20, अध्याय III, खंड पर आधारित किया। कराधान जांच समिति की रिपोर्ट का III. वहां, समिति ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और चुंगी के संबंध में बिक्री कर की तुलनात्मक खूबियों पर चर्चा करते हुए बताया कि बिक्री कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था और इसे वस्तुओं की व्यापकता पर लागू

किया जा सकता था, जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और चुंगी को लागू किया जा सकता था। यह देश के औद्योगिक उत्पादन के केवल एक सीमित हिस्से पर ही लागू होता है। समिति ने सूची II, प्रविष्टि 54 के दायरे पर कोई राय व्यक्त नहीं की। उस प्रविष्टि के तहत राज्य विधायिका गन्ने की सभी खरीद पर कर लगाने के लिए बाध्य नहीं है। यह किसी कारखाने में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए आवश्यक गन्ने की खरीद पर कर लगा सकता है। विधायिका विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने और कर के भुगतान से छूट देने में भी सक्षम है। विशेष उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं के विशेष उपचार के अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट, 1946 की धारा 6 और अनुसूची I, आइटम 23 व्यक्तिगत पहनने के लिए कपड़ों और वस्तुओं पर कर लगाते हैं। सीपी और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 2 (जे) (ए) (ii) एक पंजीकृत डीलर द्वारा माल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए इच्छित माल की बिक्री से छूट देती है।

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, वी. एपी राज्य (बछवाल, जे.)

श्री चटर्जी ने प्रस्तुत किया कि धारा 21 के तहत लगाया गया कर एक उपयोग कर था और मैकलियोड बनाम दिलवर्थ एंड कंपनी और सी.जी. नायडू एंड कंपनी, मद्रास राज्य को संदर्भित किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य विधायिका एक उपयोग कर नहीं लगा सकती थी जो अनिवार्य रूप से

इससे भिन्न था। एक खरीद कर। वकील की यह धारणा कि धारा 21 उपयोग कर लगाती है, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। धारा 21 के तहत कर योग्य घटना वस्तुओं की खरीद है, न कि जो खरीदा गया है उसका उपयोग या आनंद। ए का संवैधानिक निहितार्थ अमेरिकी बी कानून में उपयोग कर पूरी तरह से अप्रासंगिक है। मद्रास मामले में यह टिप्पणी कि संविधान की धारा 286(1) (ए) राज्य विधायिका को उपयोग कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है, गलत है। स्पष्टीकरण ने कुछ बिक्री की स्थिति तय की। इसने विधायिका को उपयोग कर लगाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की

श्री चटर्जी के एक अन्य तर्क की सराहना के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1961 के अधिनियम संख्या 45 के पारित होने से पहले 3 मार्च 1960 को राजपत्र में प्रकाशित विधेयक के अनुच्छेद 21 में उपयोग, उपभोग के लिए कारखाने के परिसर में गन्ने के प्रवेश पर उपकर लगाने का प्रावधान था या उसमें बिक्री. 13 दिसम्बर 1960 को यह न्यायालय डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य मे यूपी गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 में एक समान प्रावधान को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्यविधायिका प्रविष्टि 52, सूची II के तहत इसे अधिनियमित करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि एक कारखाने का परिसर नहीं था। प्रवेश के अर्थ के अंतर्गत एक

स्थानीय क्षेत्र। इस विभाजन को ध्यान में रखते हुए, विधेयक के पैराग्राफ 21 में संशोधन किया गया और धारा 21 को उसके वर्तमान स्वरूप में राज्यविधानमंडल द्वारा पारित किया गया। अधिनियम 30 दिसंबर, 1961 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। श्री चटर्जी ने प्रस्तुत किया कि इस संदर्भ में धारा 21 के तहत लेवी वास्तव में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए किसी कारखाने में माल के प्रवेश पर लगाया गया लेवी था। हम इस विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। चूँकि किसी कारखाने में माल के प्रवेश पर प्रस्तावित कर असंवैधानिक था, मूल विधेयक के अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया और धारा 21 को उसके वर्तमान स्वरूप में अधिनियमित किया गया। धारा 21 के तहत कर अनिवार्य रूप से माल की खरीद पर लगने वाला कर है। कर योग्य घटना किसी कारखाने में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए गन्ने की खरीद है, न कि किसी कारखाने में गन्ने का प्रवेश। चूँकि कर किसी कारखाने में गन्ने के प्रवेश पर नहीं है, यह कारखाने द्वारा उगाए गए गन्ने और कारखाने के परिसर में प्रवेश पर देय नहीं है।

श्री सेतलवाड ने कहा कि धारा 21 मुक्त व्यापार, वाणिज्य और संभोग में बाधा डालती है और संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करती है और फर्म एटी मेहताब माजिद एंड कंपनी

बनाम मद्रास राज्य, के फैसले पर भरोसा करती है। उस मामले में, न्यायालय ने माना कि मद्रास जनरल सेल्स टैक्स (टर्न ओवर और असेसमेंट) नियम, 1939 के नियम 16(2) आयातित खाल या खाल के खिलाफ भेदभाव करते हैं जिन्हें खरीदा गया था या टैन किया गया था। राज्य के बाहर उन पर अधिक कर लगाकर संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) का उल्लंघन किया गया। पी पर. 442 (एससीआर के) रघुबर दयाल, जे. ने कहा:

"इसलिए अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कर कानून व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यदि वे व्यापार के प्रवाह में बाधा डालते हैं और यदि वे नहीं हैं तो उन्हें प्रतिपूरक कर या विनियामक उपाय कहा जा सकता है। इस तरह के बिक्री कर यहां विचार को किसी भी व्यापार को विनियमित करने वाला उपाय या व्यापारिक सुविधाओं के उपयोग के लिए लगाया गया प्रतिपूरक कर नहीं कहा जा सकता है। बिक्री कर, जिसका प्रभाव एक राज्य के माल और दूसरे के माल के बीच भेदभाव करने का होता है, मुक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है व्यापार और यह तब अनुच्छेद 301 का उल्लंघन

होगा और केवल तभी मान्य होगा जब यह अनुच्छेद 304

(ए) की शर्तों के भीतर आता है।"

वह मामला तय करता है कि बिक्री कर जो अन्य राज्योंसे आयातित वस्तुओं के खिलाफ भेदभाव करता है , व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा डाल सकता है और तब तक अमान्य है जब तक कि अनुच्छेद 304 (ए) द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है। लेकिन धारा 21 के तहत लगाया गया कर किसी भी आयातित गन्ने के साथ भेदभाव नहीं करता है। धारा 21 के तहत, किसी कारखाने में उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए आवश्यक सभी गन्ने की खरीद पर समान दर से कर लगाया जाता है। राज्य में उगाए गए गन्ने और बाहर से आयातित गन्ने के बीच कोई भेदभाव नहीं है । दरअसल, अधिनियम के तहत फैक्ट्री आम तौर पर फैक्ट्री क्षेत्र में उगाए गए गन्ने को ही खरीद सकती है। वस्तुओं पर गैर-भेदभावपूर्ण कर अनुच्छेद 901 का उल्लंघन नहीं करता है जब तक कि यह सीधे तौर पर वस्तुओं की मुक्त आवाजाही या परिवहन में बाधा नहीं डालता है। अतियाबारी टी कंपनी लिमिटेडबनाम असम राज्य व अन्य,मे गजेंद्रगडकर, जे. ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहा:

"इसलिए हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अनुच्छेद 301 द्वारा

गारंटीकृत स्वतंत्रता की चौड़ाई और आयाम की सीमा

निर्धारित करने में एक तर्कसंगत और व्यावहारिक परीक्षण

लागू होगा: क्या लगाया गया प्रतिबंध सीधे या तुरंत व्यापार या उसके आंदोलन पर लागू होता है? यह है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक माल के परिवहन की मुक्त आवाजाही को बचाने का इरादा है, और यदि कोई अधिनियम ऐसे माल की आवाजाही पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाता है तो यह अनुच्छेद 301 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, और इसकी वैधता को कम किया जा सकता है। केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब यह अनुच्छेद 302 या अनुच्छेद 304 भाग XIII की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।"

आंध्र शुगर्स लिमिटेड, वी. एपी राज्य (बछवाल, जे.) 719

ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य में अनुच्छेद 301 की इस व्याख्या से असहमति नहीं जताई गई । आम तौर पर, माल की बिक्री पर कर सीधे माल की मुक्त आवाजाही या परिवहन में बाधा नहीं डालता है। धारा 21 कोई अपवाद नहीं है। यह माल की मुक्त आवाजाही या परिवहन में बाधा नहीं डालता है। और अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं है।

श्री सीतलवाड ने आगे कहा कि धारा 21 कई तरीकों से संविधान के अनुच्छेद 14 को ठेस पहुंचाती है। यह तर्क दिया गया कि एस.21 को एस.

2 (ई) के साथ पढ़ने पर वैक्यूम पैन और ओपन पैन प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले चीनी उत्पादकों के बीच भेदभाव होता है। धारा 21 के तहत, जैसा कि 1967 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा इसके संशोधन से पहले था, वैक्यूम पैन के माध्यम से चीनी का उत्पादन करने वाले कारखानों द्वारा गन्ने की खरीद पर कर लगाया गया था, लेकिन खुले पैन प्रक्रिया द्वारा खंडसारी चीनी का उत्पादन करने वाली खंडसारी इकाइयों द्वारा गन्ने की खरीद पर कर लगाया गया था। कर से पूर्णतः मुक्त थे। यहां तक कि संशोधित धारा 21 भी खंडसारी इकाइयों द्वारा गन्ने की खरीद पर कर की कम दर लगाती है। यह भी तर्क दिया गया कि गन्ने की खरीद को कर के भुगतान से छूट देकर गुड उत्पादकों के पक्ष में भेदभाव किया गया है। लेकिन उत्तरदाताओं की ओर से दायर हलफनामे से पता चलता है कि वैक्यूम पैन के माध्यम से चीनी का उत्पादन करने वाली फैक्टरियां और खुले पैन प्रक्रियाओं द्वारा चीनी का उत्पादन करने वाली खंडसारी इकाइयां अलग और अलग वर्ग बनाती हैं। वैक्यूम पैन प्रक्रिया का उपयोग करने वाला उद्योग 1932-33 से अस्तित्व में है। 1949 तक इस उद्योग पर कोई कर नहीं लगाया गया था। 1949 में जब उद्योग अच्छी तरह से स्थापित हो गया, तो मद्रास चीनी फैक्ट्री नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 14 द्वारा पहली बार इस पर कर लगाया गया। खंडसारी इकाइयाँ छोटे पैमाने पर चलती हैं उद्योग। वे हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुए हैं । 1967

तक यह उद्योग कर से मुक्त था। जब 1967 में उद्योग कुछ हद तक स्थापित हुआ तो उस पर छोटी दर से कर लगाया गया। 1965-66 में, वैक्यूम पैन प्रक्रिया अपनाने वाली फैक्टरियों ने 32 लाख टन से अधिक गन्ना खरीदा, जबकि राज्य में खांडसारी चीनी इकाइयों ने लगभग 2.70 लाख टन गन्ना खरीदा। गुड के निर्माण का वैक्यूम पैन या ओपन पैन प्रणाली द्वारा चीनी के निर्माण से कोई समानता नहीं है। यह एक कुटीर उद्योग है जिसमें व्यक्तिगत गन्ना उत्पादक अपने गन्ने को गुड में संसाधित करते हैं और इसे तैयार उत्पाद के रूप में विपणन करते हैं। हलफनामों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वैक्यूम पैन के माध्यम से चीनी का उत्पादन करने वाले कारखानों, खुले पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन करने वाली खांडसारी इकाइयों और गुड के निर्माण के लिए गन्ने का उपयोग करने वाले गन्ना उत्पादकों के बीच अंतर व्यवहार उचित है और इसका तर्कसंगत संबंध है। कराधान की वस्तु के लिए, गन्ने के उपयोगकर्ताओं के तीन वर्गों और कर का भुगतान करने की उनकी क्षमता के बीच उल्लेखनीय अंतर हैं। विधायिका लेवी के प्रयोजनों के लिए बेंत के उपयोगकर्ताओं के तीन समूहों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सकती है।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि धारा 21 (3) के तहत नए कारखानों और कारखानों को छूट देने की शक्ति, जिनका सरकार की राय में काफी विस्तार हुआ है, भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हम

इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। नये कारखानों की स्थापना एवं विद्यमान कारखानों के विस्तार को प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है। नए और विस्तारित कारखानों के पक्ष में छूट वैध विधायी नीति पर आधारित है। प्रश्न यह है कि क्या किसी कारखाने को छूट दी जानी चाहिए, और यदि हां, तो किस अवधि के लिए और यह प्रश्न कि क्या किसी कारखाने का पर्याप्त विस्तार हुआ है और यदि हां, तो ऐसे विस्तार की सीमा का निर्णय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जाहिर है, राज्य विधायिका के लिए व्यक्तिगत मामलों की खूबियों की जांच करना संभव नहीं है और कार्य राज्य सरकारको उचित रूप से सौंपा गया था, विधायिका सरकार के मार्गदर्शन के लिए अधिक कठोर मानक निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं थी। हमारा मानना है, कि धारा 21 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है।

याचिकाकर्ता ने 1967 की रिट याचिका संख्या 101 में यह तर्क दिया कि यह एक नया कारखाना था और आंध्र प्रदेश सरकार को इसे धारा 21 (3) (ए) के तहत कर के भुगतान से छूट देनी चाहिए थी। उत्तरदाताओं द्वारा विवाद का खंडन किया गया। हलफनामे इस बिंदु पर पर्याप्त सामग्री नहीं देते हैं, न ही याचिका में राज्य सरकार को छूट देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी करने के लिए कोई प्रार्थना है। ऐसी स्थिति में हम इस विषय पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझते। 1967 की रिट

याचिका संख्या 101 में याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प अन्य कार्यवाहियों में इस विवाद को उठाने के लिए खुला होगा।

परिणामस्वरूप, याचिकाएँ लागत, एक सुनवाई शुल्क के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

जी.सी.

याचिकाएं खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमति भानुप्रिया सेहरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

\*\*\*